उसका कोकोनट के पानी पर असर आएगा ही। इसलिए अल्टीमेटली हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पर जाना होगा और उसके लिए काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसलिए महोदय, वैसे ही बैठे रहने का सवाल नहीं है।

श्री टी०एन० चतुर्वेदी: धन्यवाद सभापति महोदय। मंत्री महोदय ने अभी जिक्र किया था कोकोनट कंट्रोल बोर्ड की भूमिका का। मेरे प्रश्न का "अ" भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि कोकोनट कंट्रोल बोर्ड की पुनर्रचना हो चुकी है या नहीं और मेरे प्रश्न का "ब" भाग यह है कि मैंने देखा है कि इसमें वैज्ञानिकों की जगह कोई न कोई स्थानीय नेता या राजनीतिज्ञ ही उसका अध्यक्ष होता है। क्या वे इस बात पर भी विचार करेंगे कि किसी वैज्ञानिक की, जिसे इन समस्याओं की जानकारी हो, नियुक्ति इस स्थान पर की जाए?

श्री नीतीश कुमार: सर, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन जो बात उन्होंने कही है, उसका हम ध्यान रखेंगे।

SHRI E. BALANANDAN: Sir, the explanation given by the Minister is more or less good, but there is a time factor. The Disease is prevailing in Kerala for which the Kerala Agricultural University has found that some medicine has to be applied immediately in order to prevent the spreading of this disease. Sir, the hon. Prime Minister is here. I request that the Government should not waste any more time and see that the financial asistance requested for by the State of Kerala is sanctioned immediately. Sir, in this regard, I want some response from the Prime Minister.

श्री नीतीश कुमार: सर, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले में जल्दी करने की जरूरत है इसलिए हम लोग अर्जेंट स्टेप्स उठा रहे हैं।

Legislation for the Welfare of Workers in Fish Processing Industry

*162. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR the pleased to state:

(a) whether Government propose to pass any comprehensive legislation for the welfare of the workers in fish processing industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the details regarding the steps taken by the Government to ensure minimum wage and other benefits for these workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A statement is enclosed.

Statement

These workers are already covered under the existing legislations like Minimum Wages Act, 1948, Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1979, Workmen's Compensation act, 1923 and Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Under Section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 it is the responsibility of the appropriate Governments to fix/revise the rates of Minimum Wages.

Moreover, fish processing industries employing 10 or more workers with power or 20 or more workers without power, are covered under the Factories Act, 1948. In addition, such industries employing 20 or more workers are also covered under the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952. The employees of such establishments are also entitled to Provident Fund, Pension, and Employees Deposit Linked Insurance benefits as per the provisions of the Act and schemes.

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, I had raised the issue relating to the sea-food industry. In this industry, eighty per cent of the workers are women. Exploitation of them is going on like anything. From this industry, we are getting nearly 1,300 million US$ as foreign exchange. Those who run these factories think of profit and market; the Government thinks only of foreign exchange. But what is going on in the lives of the workers? Most of them are women and they are trated like bonded labourers. There is no law to regulate their working condition. This is going on. Here, the experience is that the existing laws have failed to protect the rights of women. Sexual harassment is also going on. Your laws have failed.

If you go through the answer, you find that it has totally rejected the demands of the workers. It is not addressing their problems. So, may I know from the hon. Minister whether he would come up with new rules and regulations. The existing laws have failed. There are loopholes. They are in favour of the management. A specific answer is needed on this. Will you revise the rules and regulations which will

be more helpful to the women workers so that they are able to improve their condition to an extent?

डा॰ सत्य नारायण जटिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा है कि मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के काम में लगे हुए लोगों को ठीक प्रकार से प्रोटक्शन नहीं मिल रहा है। जैसा कि वह जानते हैं कि इन सारी बातों को सुरक्षा देने की दृष्टि से कानून प्रावधान किए गए हैं, जिनमें वर्कमैन्स कम्पनसेशन एक्ट लागू होता है, पेमैंट आफ वेजिज एक्ट लागू होता है, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट लागू होता है, फैक्टरी एक्ट लागू होता है और मिनिमम वेजिज एक्ट लागू होता है। इतना ही नहीं, जो लोग माइग्रेट करके काम करते हैं, उसमें इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट लागू होता है, कांट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलेशन) एक्ट लागू होता है। इस प्रकार से ये कानून के प्रावधान उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य का यह कहना है कि इन सारे कानूनों से मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग के कामगारों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। यह जो कानून के प्रावधान हैं इनके पालन कराने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। इनकी अनुपालना कराने की दृष्टि से वह सारा काम कर सकती हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट उनके भविष्य निधि के बारे में, उनके ईएसआई के लाभ के बारे में निश्चित रूप से विचार करती है। पूरे देश भर में जो प्रमुख तौर पर इस प्रकार के शुद्धिकरण की इकाइयां हैं, इनकी संख्या 510 है और मोटे तौर पर इनमें 60 हजार से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन सब के कल्याण की दृष्टि से, इनके वेलफेयर की दृष्टि से इन सारी बातों पर पूरा ध्यान देने का काम राज्य सरकार का है जो मिनीमम वेजिज भी उनका तय करती है।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, I am totally dissatisfied with the answer given by the hon. Minister. He is not at all serious in finding a solution to the situation. Some kind of social crime is going on there. Thousands of women workers are engaged in this. They are at the beck and call of the management. They are working up to fourteen hours a day. They work even during night. Is it permissible? It was there long years back. Now, you see, four or five big companies are doing 50% of the business. Existing laws have failed to save the interests of the workers. Women workers have to work till night, for fifteen hours or so. You have to stop that kind of a thing. You are supposed to ban work during night. If the ban is there, sexual harassment will be less. That kind of a thing should be there. The first part of my specific question is: Will you come with new rules and regulations? Second: Will you ban work during night, especially, in the case of women who work for more than fourteen hours? This is my question.

डा॰ सत्य नारायण जटिया: सभापति जी, वास्तव में जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं—जो

प्रावधान कानून में विद्यमान हैं, उनको लागू करने की बात है। महिलाओं को रात्रि में काम करना निषेध है। यदि वे विशेष परिस्थिति में, अनुमति लेकर के किसी से काम कराना चाहते हैं तो भी रात्रि में 10 बजे के बाद उनसे काम नहीं करा सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो यह कानून तोड़ना होगा। इस के लिए मौटे तौर पर जो कानून उपलब्ध हैं, उन्हें लागू करने की बात है और पहले से जो कानून विद्यमान हैं, उन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए तो निश्चित रूप से सारी बातें दूर हो सकेंगी। जहां तक इनकी शिकायतों का मामला है उसके लिए एक अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकारों को दी हैं और राज्य सरकारें उन कानूनों का पालन कराने के लिए एप्रोप्रिएट है।

MISS MABEL REBELLO: Sir, I fully agree with what Mr. Vijaya Raghavan has said. I have seen those women who are working in the fishing industry. Mostly their fingers are bleeding and sometimes their fingers are rotten. But, still they work. The money that is given to them for this work is totally inadequate. As the hon. Member has said, they have to work for longer hours. They are not provided with any gloves, masks or anything of that sort. Therefore, they are really exposed to unhygenic conditions. I feel ultimately these women will become patients of cancer or other such diseases. I would like to know whether the Government has any plan to give adequate physical appliances to these women so that their hands, which are continuously remain in saline water, do not get affected like this. Otherwise, their fingers will have to be amputated.

डॉ॰ सत्य नारायण जटिया: महोदय, माननीय सदस्या ने जो पूछा है, इसमें इनकी चिंता यह कि वहां उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। उनके कल्याण के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी.....

कुमारी मैबल रिबैलो: उनके लिए कोई मास्क नहीं है, कोई गलब्स नहीं है और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है।

डॉ॰ सत्य नारायण जटिया: श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से.....

कुमारी मैबल रिबैलो: उनकी फिंगर्स सब लॉस हो जायेंगी, खराब हो जाएंगी।

डॉ॰ सत्य नारायण जटिया: माननीय सदस्या, जो आपने शिकायत की है, उनकी कार्य

दशाओं में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, इसके लिए हम संबंधित सरकारों को आग्रह कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): यह जो माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है, यह गंभीर प्रश्न है, और मैंने स्वयं देखा है कि केरल से जो महिला कार्यकर्ता या मजदूर और प्रदेशों में जाते हैं, उनके लिए कठिनाई पैदा होती है नियमों को ठीक तरह से लागू नहीं किया जाता है; सुरक्षा के प्रश्न रहते हैं, सुविधाओं के सवाल उठते हैं। केन्द्र भी इस संबंध में अपना उत्तरदायित्व समझता है और हम यहां से एक उच्च अधिकारी भेजेंगे जो इन प्रदेशों की स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट लाएगा।

MR. CHAIRMAN: Mr. Bommai, do you want to put your question now? ....*(Interruptions)*....

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, the Labour Minister has repeatedly said that there are laws in this regard. Yes, there are laws, but they are not enforced. Here that is not the point. The Prime Minister has assured that a senior officer will be deputed to go round and report to the Government of India. It is a welcome step because women workers are paid less for the work which they are doing. They work for more hours. It is a clear exploitation of women workers. Therefore, as per the assurance of the hon. Prime Minister, if an early report is got, the Government of India can take some certain action. I welcome the assurance given by the Prime Minister. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: You can put a qustion later when we get a report in this regard. ....*(Interruptions)*.... Next Question. ....*(Interruptions)*....

Revision of Pay Scale of Section Officers of C.S.S.

*163. MISS FRIDA TOPNO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the issue of revision of scale of pay in the grade of Section Officer in the Central Secretariat Service is still under Government's consideration, if so, the stage of the matter at present;

(b) whether the Section Officers functioning as Desk Officers are still getting the Desk Officer Allowance at pre-revised; and